

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 199] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 1971/फाल्गुन 14 1892
No. 199] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 1971/PHALGUNA 14, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 8th March 1971

S.O. 1033.—The following order made by the President is published for general information:—

Whereas by a Proclamation issued on the 23rd January, 1971, under clause (1) of article 356 of the Constitution of India it has been declared that the powers of the Legislative of the State of Orissa shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

And whereas the Legislature of the State of Orissa has authorised expenditure from the Consolidated Fund of that State for the services of the financial year 1970-71;

And whereas the amount so authorised is found to be insufficient in cases of certain services and also a need has arisen in certain cases for meeting additional expenditure not contemplated in the Annual Financial Statement of that year;

And whereas the House of the People is not in session and it is necessary to authorise expenditure from the Consolidated Fund of that State pending the sanction of such expenditure by Parliament;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (c) of clause (1) of article 357 of the Constitution, I, V. V. Giri, President of India, hereby authorise that, pending the sanction by Parliament, expenditure of sums not exceeding those specified in

column 3 of the Schedule annexed, hereto and amounting in the aggregate to the sum of nine crores, thirty lakhs, fifty-eight thousand and one hundred rupees may be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Orissa towards defraying the several charges during the financial year 1970-71 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the said Schedule.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Demand No. and Services and purposes	Sums not exceeding		
		Expenditure Charged on the Consolidated Fund of the State of Orissa	Other Expenditure to be met out of the Consolidated Fund of the State of Orissa.	Total
1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
1	1—Elections and other expenditure relating to the Home Department	29,800	23,16,600	23,46,400
2	3—Police	500	500
3	4—Expenditure relating to the Planning and Coordination Department	1,15,17,000	1,15,17,000
4	5—Community Development Projects, etc.	68,19,200	58,19,200
5	7—Cultural Affairs	100	100
6	10—Pensions	13,86,700	13,86,700
7	11—Expenditure relating to the Education Department	16,100	2,900	19,000
8	12—A Text Book Press	200	200
9	13—Land Revenue	1,000	29,77,200	29,78,200
10	14—Excise	100	100
11	16—District Administration and other Expenditure relating to the Revenue Department	700	600	1,300
12	17—Expenditure relating to the Industries Department	300	300
13	17—A—Mines	1,00,000	1,00,000
14	19—Government Press and Other Expenditure relating to the Commerce Department	2,32,100	2,32,100
15	21—Tribal & Rural Welfare	300	300
16	22—Medical and Other Expenditure relating to the Health & Family Planning Department.	17,34,300	17,34,300
17	23—Public Health	1,000	400	1,400
18	24—Irrigation	27,000	79,62,800	79,89,800
19	25—Public Works	95,300	10,38,700	11,34,000
20	26—State Legislature	14,800	91,000	1,05,800
21	27—Public Works, Common Establishment	9,000	8,56,100	8,65,100
22	28—Electricity Schemes	200	200
23	29—Taxes on Vehicles	1,30,700	1,30,700
24	30—Transport Schemes	5,600	23,60,000	23,65,600
25	31—Forest	3,00,000	3,00,000
26	32—Fisheries	200	200
27	33—Co-operation and Marketing	2,000	..	2,000
28	34—Expenditure relating to the Urban Development Department	22,88,700	22,88,700
29	35—Animal Husbandry	91,200	91,200
30	37—Agriculture	1,900	1,900
31	38—Supply Department	600	..	600
32	Interest on Debt and other Obligations	400	..	400
33	Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt.	71,93,800	..	71,93,800
34	40—Community Development Projects	79,200	79,200
35	41—Loans to Local Funds, Government Servants, etc.	100	100

1	2	3	Rs.	Rs.	Rs.
36	42-Compensation for Abolition of Zamindari System and Other Expenditure relating to the Revenue Department.	14,03,700	14,63,700
37	43-Multipurpose River, Irrigation & Electricity Schemes	99,52,200	99,52,200
38	44-Agricultural Improvement and Research	2,50,000	2,50,000
39	45-Government Trading Schemes	46,700	46,700
40	46-Road and Water Transport Schemes	48,600	48,600
41	47-Capital Expenditure relating to Public-Health and Urban Development Department	10,00,100	10,00,100
42	48-Capital Outlay on Industrial Development	36,03,300	35,03,300
43	49-Hirakud Dam Project	5,00,000	5,00,000
44	53-Capital Expenditure relating to Home Department	1,00,000	1,00,000
45	54-Capital Outlay on Forests	10,00,000	10,00,000
46	55-Share Capital Contribution and Loans to Co-operative Organisations.	22,52,000	22,52,000
47	58-Capital Expenditure relating to the Grama Panchayat Department	100	100
48	59-Capital Expenditure relating to Health Department	41,78,000	41,78,000
49	60-Capital Outlay on Public Works	76,500	..	87,88,900	88,65,400
50	62-Capital Expenditure relating to Tribal & Rural Welfare Department	12,18,000	12,18,000
51	Permanent Debt (Repayment)	25,00,000	25,00,000
52	Loans from the Central Government (Repayment)	63,93,600	63,93,600
TOTAL			1,64,13,900	7,66,44,200	9,30,58,100

(Sd.) V. V. G IRI,
President.

[No. F. 3(2)-FCC/71]

B. MAITHREYAN,
Jt. Secy.

NEW DELHI,
Dated 8th March, 1971.

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1971

एस० नो० 1०33.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश ग्राम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन 23 जनवरी, 1971 को जारी की गयी उद्घोषणा के द्वारा यह घोषित किया गया है कि उड़ीसा के विधान-मण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जा सकेगा ;

और चूंकि उड़ीसा राज्य के विधान-मण्डल ने 1970-71 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने को प्राधिकृत किया है ;

और चूंकि कुछ सेवाओं के मामलों में इस प्रकार प्राधिकृत व्यय की रकम कम पड़ गयी है और साथ ही कुछ मामलों में ऐसे अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पैदा हो गयी है जिसकी कल्पना उम वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं की गयी थी;

और चूंकि लोक सभा का सत्र नहीं हो रहा है और जब तक राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने को संसद द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाता तब तक उससे व्यय किये जाने की मंजूरी देना आवश्यक है ;

इसलिए, अब संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उप-खंड (ग) के अनुसार, मैं, भारत का राष्ट्रपति, बी० बी० गिरि, एतद्द्वारा इस बात का प्राधिकार प्रदान करता हूँ कि इस आदेश के साथ लगायी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में 1970-71 के वित्तीय वर्ष में होने वाले अनेक प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए, उड़ीसा राज्य की समेकित निधि से, संसद की मंजूरी मिलने तक, इतनी रकम खर्च की जायें जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित रकमों से अधिक नहीं और जिनका जोड़ नौ करोड़, तीस लाख, अठावन हजार एक सौ रुपया है ।

अनुसूची

क्रम मांग संख्या और सेवाएं और

निम्नलिखित रकमों से अधिक नहीं

सं०	प्रयोजन	उड़ीसा राज्य की समेकित निधि पर प्रभावित व्यय	उड़ीसा राज्य की समेकित निधि जोड़ से किया जाने वाला अन्य	
1	2	3		
	रु०	रु०	रु०	
1	1-गृह विभाग के सम्बन्ध में चुनाव संबंधी और अन्य व्यय	29,800	23,16,600	23,46,400
2	3-पुलिस	..	500	500
3	4-आयोजन और समन्वय विभाग से सम्बन्धित व्यय	..	1,15,17,000	1,15,17,000
4	5-सामुदायिक विकास प्रायोजनाएँ आदि	..	68,19,200	68,19,200
5	7-सांस्कृतिक कार्य	..	100	100
6	10-पैशन	..	13,86,700	13,86,700
7	11-शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में व्यय	16,100	2,900	19,000
8	11-क-पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	..	200	200
9	13-भू-राजस्व	1,000	29,77,200	29,78,200
10	14-उत्पादन शुल्क	..	100	100
11	16-जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	700	600	1,300

1	2	3	
12	17-उद्योग विभाग से संबंधित व्यय ..	300	300
13	17-क-खाने ..	1,00,000	1,00,000
14	19-सरकारी मुद्रणालय और वाणिज्य विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय ..	2,32,100	2,32,100
15	21-आदिम जाति और ग्राम्य कल्याण ..	300	300
16	22-स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग से संबंधित चिकित्सा और अन्य व्यय ..	17,34,300	17,34,300
17	23-लोक स्वास्थ्य 1,000	400	1,400
18	24-सिंचाई 27,000	79,62,800	79,89,800
19	25-लोक निर्माण कार्य 95,300	10,38,700	11,34,000
20	26-राज्य विधान-मण्डल 14,800	91,000	1,05,800
21	27-लोक निर्माण कार्य सामान्य प्रतिष्ठान 9,000	8,56,100	8,65,100
22	28-विद्युत योजनाएं ..	200	200
23	29-मोटर गाड़ियों पर कर ..	1,30,700	1,30,700
24	30-परिवहन योजनाएं 5,600	23,60,000	23,65,600
25	31-वन ..	3,00,000	3,00,000
26	32-मीनक्षेत्र ..	200	200
27	33-सहकारिता और विपणन 2,000	..	2,000
28	34-तगर विकास विभाग के सम्बन्ध में व्यय ..	22,88,700	22,88,700
29	35-पशु-पालन ..	91,200	91,200
30	37-कृषि ..	1,900	1,900
31	38-पूर्ति विभाग 600	..	600
32	ऋण और अन्य देनदारियों पर व्याज 400	..	400
33	ऋण में कमी या उससे बचने के लिए विनि-योग 71,93,800	..	71,93,800
34	40-सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं ..	79,200	79,200
35	41-स्थानीय निधियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण ..	100	100
36	42-जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए मुआवजा और राजस्व विभाग से संबंधित अन्य व्यय ..	14,63,700	14,63,700
37	बहुप्रयोजनी नदी, सिंचाई और विद्युत योजनाएं ..	99,52,200	99,52,200

1	2	3	
38	44—कृषि सुधार और अनुसंधान ..	2,50,000	2,50,000
39	45—राज्य व्यापार योजनाएं 46,700	46,700
40	46—सड़क और जल परिवहन योजनाएं ..	48,600	48,600
41	47—लोक स्वास्थ्य और नगर विकास विभाग से सम्बन्धित पूंजीगत व्यय ..	10,00,100	10,00,100
42	48—औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	36,03,300	36,03,300
43	49—हीराकुण्ड बांध प्रायोजना ..	5,00,000	5,00,000
44	53—गृह विभाग से सम्बन्धित पूंजीगत व्यय ..	1,00,000	1,00,000
45	54—बनों पर पूंजी परिव्यय ..	10,00,000	10,00,000
46	55—सहकारी संगठनों की श्रम पर पूंजी में भ्रंशदान और उन्हें ऋण ..	22,52,000	22,52,000
47	58—ग्राम पंचायत विभाग के सम्बन्ध में पूंजीगत व्यय ..	100	100
48	59—स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में पूंजीगत व्यय ..	41,78,000	41,78,000
49	60—लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय 76,500	87,88,900	88,65,400
50	62—आदिम जाति और ग्राम्य कल्याण विभाग के सम्बन्ध में पूंजीगत व्यय ..	12,18,000	12,18,000
51	स्थायी ऋण (परिशोधन) 25,00,000	25,00,000
52	केन्द्रीय सरकार से ऋण (परिशोधन) 63,93,600	63,93,600
जोड़		1,64,13,900	7,66,44,200 9,30,58,100

नई दिल्ली-
8 मार्च, 1971

बी० बी० गिरी,
राष्ट्रपति ।

[सं० एफ० 3(2)-एफ० सी० सी०/71]

बी० मैन्नेयन,
संयुक्त सचिव ।